कवि राज और अन्य

बनाम

जम्मू और कश्मीर राज्य व अन्य

(2013 की सिविल अपील संख्या 162)

9 जनवरी, 2013

[डी. के. जैन और जगदीश सिंह खेहर, न्या.]

सेवा कानून - संवर्ग से परे नियुक्ति (या स्थानांतरण) (या मूल विभाग) - अपीलार्थियों का चयन और नियुक्ति सहायक सर्जनों के रूप में - लेकिन सहायक सर्जनों की पदस्थापन्न के संबंध में स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रिक्त पदों के विरूध पदस्थापित किया गया। चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य के पश्चाततवर्ती आदेश के द्वारा अपीलार्थियों को उनके मूल विभाग निदेशालय स्वास्थ्य सेवा में भेज दिया गया- अपीलार्थियों द्वारा अभ्याक्रमण - उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर आदेश को अपास्त कर दिया कि कॉलेज में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नहीं थी और तदनुसार उनके मूल विभाग में वापसी का कोई प्रश्न ही नहीं था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा निर्णय पलट दिया गया - अपील पर निर्धारितः यद्यपि सहायक सर्जनों के पद राज्य सरकार

के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए थे, उक्त विभाग में दो स्वतंत्र निदेशालय शामिल थे, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय - स्पष्टतः, तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ताओं को वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में नियुक्त किया गया था, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में - सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनकी पदस्थापन्न निश्चित रूप से उनके मूल कैडर से परे थी और इसलिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से थी - मात्र यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं की सहमति उनसे पहले नहीं मांगी गई थी सरकारी मेडिकल कॉलेज में पदस्थापन्न का कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ा - तदनुसार, अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग, यानी, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन की पुष्टि की गई।

सेवा कानून -संवर्ग (या मूल विभाग) से परे नियुक्ति (या स्थानांतरण) कर्मचारी की सहमति-प्रासंगिकता और अवधारण अभिनिर्धारितः मोटे तौर पर, एक कर्मचारी को केवल उस पद पर पदस्थापित (या स्थानांतरित) किया जा सकता है जिसके विरूध उसे नियुक्त किया गया है - एक कर्मचारी, जिस विभाग में वह नियुक्त है उसके अलावा किसी अन्य विभाग में उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी कर्मचारी की पदस्थापन्न (या स्थानांतरण) की अनुमेय नहीं होगी - लेकिन संवर्ग (और/या मूल विभाग) से परे पदस्थापन्न की इच्छा को स्पष्ट रूप से मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है और इसे विवक्षित माना जा सकता है

भारत का संविधान, 1950 -अनुच्छेद 141 -सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया गया अभिनिर्धारण – अभिनिर्धारित प्रतिपादना को विधिक रूप से अन्य समान स्थिति वाले पक्षकारों तक भी विस्तारित किया गया क्योंकि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना गया था।

अपीलकर्ताओं का चयन व नियुक्ति सहायक सर्जन के रूप में की गई -स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सहायक सर्जनों की पदस्थापन्न से संबंधित एक सरकारी आदेश 17.7.1997 को जारी किया गया था। सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 के अनुरूप, प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने एक कार्यालय आदेश दिनांक 30.12.1997 द्वारा सभी अपीलकर्ताओं को सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रिक्त पदों के विरूध जम्मू (और उक्त कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में) पदस्थापित कर दिया। हालाँकि, दिनांक 7.1.1998 के आदेश द्वारा, प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग, अर्थात्

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में वापस कर दिया। आदेश दिनांक 7.1.1978 को अपीलार्थियों द्वारा मुख्य रूप से इस आधार पर उच्च न्यायालय के समक्ष अभ्याक्रमण किया गया था कि सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिकल कॉलेज, जम्मू को, अपीलार्थयों का नियुक्ति प्राधिकारी होने के कारण, आदेश दिनांक 7.1.1978 को जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने दिनांक 7.1.1998 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति से पहले संबंधित कर्मचारियों की सहमति अनिवार्य थी; और इस मामले में सहमति के अभाव ने स्थापित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नहीं थी और तदनुसार उनके मूल विभाग वापस प्रत्यावर्तन का कोई सवाल ही नहीं था। एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकालने के लिए दिनांक 17.7.1997 के सरकारी आदेश पर भी भरोसा किया, कि अपीलकर्ताओं की सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में पदस्थापन्न उनके कैडर से परे नहीं थी। इसके पैराग्राफ 5(एफ) का हवाला देते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न उनके रोजगार की शर्तों के दायरे में थी। हालाँकि निर्णय को डिवीजन बेंच अपीलों द्वारा रद्द कर दिया गया था और इसलिए वर्तमान अपीले

न्यायालय द्वारा अपील को अभिनिधारित किया

1 यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति मूल रूप से चिकित्सा शिक्षा निदेशक के अधीन एक संवर्ग में की गई थी। निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हुई थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में उनकी पदस्थापन्न निश्चित रूप से उनके मूल कैडर से परे थी और इसलिए प्रतिनियुक्ति के माध्यम से थी।

[पैरा 18] [640-जी-एच; 641-ए]

2. हालांकि यह स्पष्ट है कि सहायक सर्जन के पद राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए थे, यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त विभाग में दो स्वतंत्र निदेशालय शामिल हैं, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय। दोनों निदेशालयों में से प्रत्येक के कर्मचारी नियमों के एक अलग सेट द्वारा शासित होते हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों में सहायक सर्जन के पद नहीं हैं। सहायक सर्जन का कैडर केवल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के राजपत्रित कर्मचारियों पर लागू भर्ती नियमों में पाया जाता है। दूसरे, प्रतिवादियों के विद्वान वकील के हाथों यह दावा किया गया कि जब अपीलकर्ताओं का चयन किया गया और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में तैनात किया गया तो सहायक सर्जन के कोई पद नहीं थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय पर विवाद नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में सहायक सर्जन के किसी भी पद के अभाव में, यह अनुमान लगाना असंभव है कि अपीलकर्ता (जिन्हें सहायक सर्जन के पदों के विरुद्ध चुना गया था) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा, लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलकर्ताओं के चयन के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 12.8.1997 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। उपरोक्त नियुक्ति आदेश का एक प्रासंगिक उद्धरण ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। इसके

अवलोकन से पता चलता है कि जिन अभ्यर्थीं को सहायक सर्जन के रूप में चुना गया था, और वे जम्मू क्षेत्र से थे, उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को रिपोर्ट करना था। जबकि, कश्मीर क्षेत्र से संबंधित लोगों को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, कश्मीर को रिपोर्ट करना था। जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक, संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालयों में प्रशासनिक कमान श्रृंखला के प्रभारी माने जाते हैं। यह स्वयं प्रदर्शित करता है, कि

अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में थी, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में। चौथा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा दिनांक 30.12.1997 को जारी आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं को सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात किया जा रहा था। सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के पद सहायक सर्जन के पदों से अलग और अलग हैं। सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के पद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पदों के कैडर में शामिल हैं। अपीलकर्ताओं की सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में पदस्थापन्न यह भी दर्शाती है कि उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के भीतर नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के बाहर के पदों पर थी। इसके अलावा, दिनांक 7.1.1998 के आक्षेपित आदेश में भी कहा गया है कि अपीलकर्ताओं को अस्थायी रूप से तैनात किया जा रहा था "... स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से, जम्मू..."

सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में डॉक्टरों की कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। छठा, आदेश दिनांक 7.1.1998 (ऊपर पैराग्राफ 5 में निकाला गया) के क्रम संख्या 2 पर समर्थन से पता चलता है, कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ताओं को निदेशालय में वापस भेज दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाएँ, उक्त सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सातवें, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के दिनांक 20.4.1998 के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) स्वास्थ्य सेवाओं के दो निदेशकों द्वारा की गई थी। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए, उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए अपीलकर्ताओं को चुना और नियुक्त किया गया था। अंत में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह अखण्डित दावा है कि अपीलकर्ताओं का वेतन उस पूरी अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से लिया जाता रहा, जिस अवधि के दौरान अपीलकर्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात रहे। जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में)

यदि अपीलकर्ता वैध रूप से अपने कैडर के भीतर काम कर रहे होते, तो उनका वेतन निस्संदेह चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के फंड से आहरित होता। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कोष से अपीलकर्ताओं को वेतन के संवितरण के आधार पर, अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहायक सर्जन के कैडर का वास्तविक कर्मचारी माना जाना चाहिए। इसलिए इसमें किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है

कि अपीलकर्ताओं को वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में नियुक्त किया गया था, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में।

[पैरा 19] [641-बी-एच; 642-ए-एच; 643 ए-सी]

3.मात्र तथ्य, कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में उनके पदस्थापन्न से पहले अपीलकर्ताओं की सहमति नहीं मांगी गई थी, वर्तमान विवाद पर कोई निर्णायक प्रभाव नहीं डालता है। मोटे तौर पर, एक कर्मचारी को केवल उस पद पर पदस्थापित (या स्थानांतरित) किया जा सकता है जिसके विरूध उसे नियुक्त किया गया है। इससे उनके प्रमुख नियोक्ता के तहत पदों के संवर्ग के भीतर उनका पदस्थापन्न सुनिश्चित हो जाएगा। हालाँकि, उनके पदस्थापन्न को उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों द्वारा अलग-अलग तरीके से विनियमित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी नियम के अभाव में, किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा/तत्परता के बिना उस संवर्ग से बाहर पदस्थापित (या स्थानांतरित) नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए उसका चयन किया गया है। इसलिए, एक कर्मचारी की पदस्थापन्न (या स्थानांतरण), किसी अन्य विभाग में की जाती है जिसके लिए उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध नियुक्त किया गया है, उसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन कैडर (और/या मूल विभाग) से परे पदस्थापन्न की इच्छा स्पष्ट रूप से मांगी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह विवक्षित हो सकती है. इसे लिखित सहमति की

प्रकृति में होना आवश्यक नहीं है। कैडर (या मूल विभाग) से परे पदस्थापन्न (या स्थानांतरण) की सहमति का अनुमान कर्मचारी के आचरण से लगाया जा सकता है, जो ऐसी पदस्थापन्न/स्थानांतरण का विरोध या प्रतिरोध नहीं करता है। वर्तमान विवाद में, अपीलकर्ताओं को प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा दिनांक 30.12.1997 को पदस्थापन्न आदेश जारी किए गए थे।

उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, और सहायक सर्जन के रूप में चयन और नियुक्ति के बावजूद, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में वरिष्ठ/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अब भी, वे निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में पदों के विरुद्ध सेवा जारी रखना चाहते हैं। उधार निदेशालय के साथ सेवा करने की उनकी इच्छा/तत्परता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। अपीलकर्ताओं की सहमति मौन और निर्विवाद है। [पैरा 20] [643-ई-एच; 644-ए-सी]

4. प्रस्तुत मामले में, एकल न्यायाधीश के फैसले के परिणामस्वरूप, जिसमें अपीलकर्ताओं के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के दिनांक 7.1.1998 के प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया था, उत्तरदाताओं द्वारा यहाँ दो पत्र पेटेंट अपीलें दायर की गईं थीं। पहली लेटर्स पेटेंट अपील में, 18 सहायक सर्जनों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, जबकि, दूसरे लेटर्स पेटेंट अपील में, 24 सहायक सर्जनों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

पहली लेटर्स पेटेंट अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था और इसे कभी भी बहाल नहीं किया गया था। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा एक तकनीकी दलील दी गई थी कि 18 सहायक सर्जनों के संबंध में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अंतिम रूप ले चुका है और 18 सहायक सर्जनों के संबंध में बाध्यकारी प्रभाव को शेष 24 सहायक सर्जनों तक बढ़ाया जाना चाहिए। हालाँकि, जहाँ तक 24 सहायक सर्जनों से संबंधित मामले का संबंध है, 24-2-2006 को उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए निर्णय की इस न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर पुष्टि की गई है। 24 सहायक सर्जनों (जिनका दावा दिनांक 24.2.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा तय किया गया है) से संबंधित निर्णय कानून की घोषणा का गठन करता है, और भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है। 24 सहायक सर्जनों (जिनका दावा उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा तय किया गया था) के संबंध में दिए गए निर्धारण का विस्तार, यदि अनुमेय हो,तो इसे अन्य 18 सहायक सर्जनों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। आम तौर पर, ऐसी स्थिति में जब प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच कोई निर्णय अंतिम हो जाता है, तो किसी त्रुटि को सुधारने के लिए भी, जो बाद के निर्णय से उत्पन्न होती है, मुद्दे को फिर से खोलना वैध नहीं है। हालाँकि, मौजूदा विवाद में तथ्यात्मक स्थिति थोड़ी अलग है। जिन सहायक सर्जनों के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी, वे भी इस न्यायालय के समक्ष हैं और उन्हें भी सुनवाई का अवसर दिया गया है। चूँकि वे सभी इस न्यायालय के समक्ष

हैं, और वकील के माध्यम से उनका प्रतिनिधित्व किया गया है, निस्संदेह, प्रस्तुत विवाद में योग्यता के आधार पर निर्णय उन तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। चूंकि इस तरह का विकल्प वर्तमान मामले में किया जा सकता है, जिस प्रतिपादना को कानूनी माना गया है, उसे समान रूप से स्थित अन्य लोगों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए। उस आदेश को लागू करना अकल्पनीय होगा, जिसे उचित नोटिस और सुनवाई के बाद रद्द कर दिया गया है।

[पैरा 22,24,25] [644] एफ-एच; 645-ए-सी; 646-बी-डी, ई-एफ, जी-एच; 647-ए-बी]

5. अपीलार्थियों का उनके मूल विभाग यानी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन, जम्मू की पुष्टि की गई है। [पैरा 26] [647-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 162/2013

जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू के द्वारा एल. पी. ए. (एस. डब्ल्यू.) संख्या 88/2000 में दिनांक 24.02.2006 के निर्णय और आदेश से के साथ सी. ए. सं. 163/2013

सी. ए. सुंदरम, नर हरि सिंह, विकास मेहता, माधवी चौधरी, जफर इनायत, रोहिणी मूसा अपीलार्थी की ओर से।

सुनील फर्नांडीस, आस्था शर्मा, वर्निका तोमर, इंशा मीर प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय द्वारा दिया गया था

जगदीश सिंह खेहर, न्या. 1. अनुमति दी गई।

2.सहायक सर्जनों के पदों के सृजन के परिणामस्वरूप, जम्मू और कश्मीर राज्य के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जम्मू और कश्मीर लोक सेवा आयोग (इसके बाद इसे "लोक सेवा आयोग" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) को असिस्टेंट सर्जन के 1255 पदों पर भर्ती का एक अध्यपेक्षा भेजी। उपरोक्त अध्यपेक्षा के आधार पर, लोक सेवा आयोग ने 2200-4000 रुपये के वेतनमान में सहायक सर्जन के 1255 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 31.12.1996 को एक अधिसूचना जारी की। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर, 2.1.1997 को समाचार पत्रों में एक विज्ञापन छपा जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित सहायक सर्जन के 1255 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए।

3. जून, 1997 में लोक सेवा आयोग ने चयन प्रक्रिया को पूरा करते हुए, सफल अभ्यर्थीों की एक चुनिंदा सूची तैयार की। यहाँ अपीलार्थियों के नाम, सफल अभ्यर्थीों की सूची में दिखाये गये। लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक सर्जन के रूप में अपीलकर्ताओं के चयन के परिणामस्वरूप, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने दिनांक 12.8.1997 को एक आदेश जारी कर अपीलकर्ताओं को सहायक सर्जन के

विज्ञापित पदों पर नियुक्त किया। वर्तमान विवाद से संबंधित पूर्वोक्त आदेश का एक उद्धरण यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"जम्मू क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी आगे की पदस्थापन्न के लिए निदेशक स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को और कश्मीर क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थी निदेशक स्वास्थ्य सेवा कश्मीर को रिपोर्ट करेंगे। जहां तक प्रवासी अभ्यर्थीं का संबंध है, वे अगले आदेश के लिए निदेशक, स्वास्थ्य सेवा जम्मू को रिपोर्ट करेंगे।"

यह विवाद का विषय नहीं है कि दिनांक 12 8.1997 के नियुक्ति आदेश को आगे बढ़ाते हुए, सभी अपीलकर्ताओं ने निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू क्योंकि वे सभी जम्मू से संबंधित थे। अगला कदम, जैसा कि निकाले गए नियुक्ति आदेश के हिस्से से स्पष्ट है, अपीलार्थियों का पदस्थापन्न वास्तविक था।

4. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सहायक सर्जनों की तैनाती से संबंधित एक सरकारी आदेश 17.7.1997 को जारी किया गया था। उपरोक्त सरकारी आदेश का पैराग्राफ 5 प्रासंगिक है, और तदनुसार इसे निम्न प्रकार उद्धरित किया जा रहा है:

"5. सामान्य श्रेणी के विरुद्ध नियुक्त चिकित्सक निम्नलिखित आदेशों में विभिन्न अस्पतालों में तैनात किया जाए:

ए) एलोपैथिक औषधालय

बी) प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस अस्पताल;

सी) सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र;

डी) उप-जिला अस्पताल;

इ) जिला अस्पताल;

एफ) जम्मू और श्रीनगर के अस्पताल जिनमें शाम/शहरी क्लिनिक और उसके बाद चिकित्सा शिक्षा और अन्य संगठन शामिल हैं;

जी) सर्जनों को केवल ऐसे अस्पतालों में तैनात किया जाएगा जहां ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध हैं और अस्पताल सरकारी इमारतों में स्थित हैं।"

यहां ऊपर दिए गए पैराग्राफ 5 के उप-पैराग्राफ (एफ) में किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं है, कि सहायक सर्जनों को शाम / शहरी क्लीनिकों सहित जम्मू और श्रीनगर के अस्पतालों में, "... और उसके बाद ...", चिकित्सा शिक्षा और अन्य में तैनात किया जा सकता है। संगठन सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 के अनुरूप, प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने एक कार्यालय आदेश दिनांक 30.12.1997 द्वारा, सभी अपीलकर्ताओं को सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू (और उक्त कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में) सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रिक्त पदों पर तैनात किया।

5. 30.12.1997 को अपीलकर्ताओं की सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में पदस्थापन्न के बावजूद; उसके एक सप्ताह के भीतर, दिनांक 7.1.1998 के एक आदेश द्वारा, प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में वापस कर दिया। दिनांक 7.1.1978 के प्रस्तुत आदेश पर सबसे पहले अपीलकर्ताओं ने जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय (इसके बाद इसे "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के समक्ष चुनौती दी थी। यह अब इस न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा चुनौती का विषय है। चूँकि वर्तमान विवाद दिनांक 7.1.1998 के आदेश से संबंधित है, जिसके तहत अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेजने/वापस भेजने का आदेश दिया गया था, इसे यहां नीचे उद्धरित किया जा रहा है:

"इस संस्थान में विभिन्न विशिष्टताओं में हाउस सर्जनों की नियुक्ति के परिणामस्वरूप, सहायक सर्जन, जिन्हें सरकार में डॉक्टरों की कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू से अस्थायी रूप से तैनात किया गया था। मेडिकल कॉलेज, जम्मू को इसके मूल विभाग में वापस कर दिया गया है। संलग्न अनुबंध- I में सूचीबद्ध डॉक्टरों को आज 7 जनवरी, 1998 को पूर्वाह्न में निदेशक स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के निर्देश के साथ कार्यमुक्त किया गया है।"

ऊपर दिए गए आदेश के अवलोकन से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में अपीलकर्ताओं के कथित प्रत्यावर्तन के आधार का पता चलता है। प्रथमतः, अपीलकर्ताओं के मूल विभाग को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के रूप में वर्णित किया गया है। द्वितीय, अपीलकर्ताओं की सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में पदस्थापन्न का खुलासा किया गया

अर्थात्, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में डॉक्टरों की कमी की आवश्यकता को पूरा करना और तीसरा, उक्त पदस्थापन्न को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू से अस्थायी तैनाती के रूप में दर्शाया गया था। ऊपर निकाले गए मुख्य आदेश दिनांक 7.1.1998 के अलावा, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को उपरोक्त आदेश के क्रम संख्या 2 पर किए गए समर्थन को पुनः प्रस्तुत करना भी प्रासंगिक है। इसलिए इसे नीचे उद्धरित किया जा रहा है:।

"2.निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, जम्मू। यह स्वास्थ्य सेवाओं में तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायक सर्जनों को निदेशालय में वापस भेजने के उनके मौखिक अनुरोध के संदर्भ में है।

उपरोक्त पृष्ठांकन के अवलोकन से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में अपीलकर्ताओं के कथित प्रत्यावर्तन के चतूर्थ कारण का खुलासा होता है, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा विभाग की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए।

6. दिनांक 7.1.1998 के आदेश को चुनौती देने के लिए जिसके तहत अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में वापस भेज दिया गया था, उच्च न्यायालय के समक्ष तीन रिट याचिकाएं दायर की गईं। रिट याचिकाओं का विवरण यहां नीचे दिया जा रहा है:

i) डॉ. शाज़िया हामिद बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (एसडब्ल्यूपी संख्या 35/98)

ii) डॉ.रजनी मल्होत्रा बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (एसडब्ल्यूपी संख्या 36/98)

iii) डॉ.सरिता बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (एसडब्ल्यूपी संख्या 37/98)

उपरोक्त रिट याचिकाओं पर विचार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने 8.1.1998 को निम्नलिखित अंतरिम निर्देश जारी किए:

"याचिका कर्ताओ की शिकायत यह है कि उन्हें निदेशक स्वास्थ्य सेवा, जम्मू द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू में तैनात किया गया है और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने उन्हें आगे मेडिकल कॉलेज, जम्मू में तैनात किया है। उन्हें प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के व्यक्ति द्वारा कार्यमुक्त किया जा रहा है, जिसके पास उन्हें स्थानांतरित करने और निदेशक स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को वापस रिपोर्ट करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करें, सीएमपी में भी नोटिस जारी करें।

इस बीच, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे आपत्तियां दायर होने और इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने तक याचिकाकर्ताओं की स्थिति से छेड़छाड़ न करें।

हमें सूचित किया गया है कि उक्त अंतरिम निर्देशों के अनुपालन में, सभी अपीलकर्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे।और तब से, वर्तमान समय तक, उनके खिलाफ आक्षेपित आदेश (उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा पारित) पारित होने के बावजूद, अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न अपरिवर्तित रही है। अब भी, वे सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं।

7. यहां यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि मुख्य आधार जिस पर अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 7.1.1998 के आक्षेपित आदेश पर आपत्ति जताई थी, वह यह था कि इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था। इस संबंध में, अपीलकर्ताओं का मामला यह था कि सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपीलकर्ताओं का नियुक्ति प्राधिकारी है; प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, जम्मू को दिनांक 7.1.1998 का आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र

नहीं था। हमें ऐसा लगता है कि अपीलकर्ताओं के आदेश पर उठाए गए हमले के मुख्य आधार से उबरने के लिए, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 20.4.1998 को उसी प्रभाव और परिणाम के साथ एक और आदेश जारी किया।

उपरोक्त आदेश यहां भी निकाला जा रहा है:

"जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए विशेष भर्ती अभियान कार्यक्रम के तहत 1996 के सरकारी आदेश संख्या 129-एचडी दिनांक 4.12.96 के तहत सहायक सर्जनों के 1230 पद सृजित किए गए थे और उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए लोक सेवा आयोग को भेजा गया था।

जबकि लोक सेवा आयोग ने अपने पत्र संख्या पीएससी/1/डॉ/एएस/5-96 दिनांक 10.6.97 के माध्यम से सहायक सर्जन की नियुक्ति के लिए 1097 उम्मीदवारों के एक पैनल की सिफारिश की थी।

जबकि स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 1097 सहायक सर्जनों के पक्ष में नियुक्ति आदेश जारी किए और स्वास्थ्य सेवाओं के दो निदेशकों को सरकारी आदेश संख्या 635 एचएमई का 1997 दिनांक 17.7.97. में सन्निहित दिशानिर्देशों के अनुसार इन डॉक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर तैनात करने का निर्देश दिया।

जबकि स्वास्थ्य सेवाओं के दो निदेशकों ने स्थायी सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों और कार्यालयों में बड़ी संख्या में नई नियुक्तियों को कार्य करने के लिए_प्रतिनियुक्त/संलग्न/समायोजित/विस्तारित किया, जिससे विशेष भर्ती अभियान का उद्देश्य ही विफल हो गया।

इसलिए अब सार्वजनिक हित और स्वास्थ्य देखभाल में उक्त सहायक सर्जनों को उन स्थानों से तत्काल प्रभाव से अलग किया जाता है जहां उन्हें प्रतिनियुक्त/संलग्न/समायोजित या काम करने के लिए विस्तृत किया गया है, जैसा भी मामला हो और वे स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित निदेशकों को रिपोर्ट करेंगे जो उन्हें सरकारी आदेश संख्या 635 एचएमई 1997 दिनांक 17.7.97 में विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार सख्ती से पोस्ट करेंगे और सकारात्मक रूप से एक पखवाड़े के भीतर प्रशासनिक विभाग को अनुपालन रिपोर्ट देंगे।

यहां ऊपर दिया गया आदेश सहायक सर्जन के रूप में उनके चयन के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की अंतिम पदस्थापन्न के लिए घटनाओं का सटीक अनुक्रम बताता है। इस बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि दिनांक 20.4.1998 का आदेश इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अपीलकर्ताओं की मूल पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) स्वास्थ्य निदेशक द्वारा की गई थी। सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए सेवाएँ, और इसके अलावा, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू को उनका प्रत्यावर्तन सार्वजनिक हित में था।

8. 28.5.1998 को उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने सभी तीन रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया (जिसमें दिनांक 7.1.1998 के आदेश को चुनौती दी गई थी)। विद्वान एकल न्यायाधीश की समझ के अनुसार, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति से पहले संबंधित कर्मचारियों की सहमति अनिवार्य थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, सहमति की अनुपस्थिति ने स्थापित किया कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में उनकी नियुक्ति, जम्मू, (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में), प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नहीं था। चूँकि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं की सहमति दिनांक 30.12.1997 के आदेश के तहत उनकी पदस्थापन्न से पहले प्राप्त नहीं की गई थी, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला, अन्य बातों के साथ, कि अधिकारियों ने गलत तरीके से मान लिया था, कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में), प्रतिनियुक्ति के माध्यम से था। तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग में वापस भेजने का कोई सवाल ही नहीं है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में अपीलकर्ता का मूल विभाग शामिल था। इसके आधार पर, विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में अपीलकर्ताओं के प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन में कानूनी मंजूरी का अभाव था।

9. विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी इस पर भरोसा किया कि सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि

अपीलकर्ताओं की सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में पदस्थापन्न उनके कैडर से परे नहीं थी। इसके पैराग्राफ 5(एफ) का उल्लेख करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न उनके रोजगार की शर्तों के दायरे में थी।

10. उपरोक्त के अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जम्मू के पास अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू को वापस भेजने/वापस भेजने के दिनांक 7.1.1998 के आक्षेपित आदेश जारी करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस संबंध में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने महसूस किया कि प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू ने विभाग के प्रमुख के रूप में अपनी क्षमता में दिनांक 7.1.1998 को आदेश पारित किया था, जो तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति के अनुरूप नहीं था।

11. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निष्कर्षों का सारांश निम्न प्रकार दिया:

"उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाता है कि:

i) याचिकाकर्ताओं को सहायक सर्जन के रूप में नियुक्त किया गया।

ii) स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के आयुक्त/सचिव ने 17 जुलाई, 1997 को स्पष्ट आदेश पारित किया कि याचिकाकर्ताओं को जम्मू के अस्पतालों में नियुक्त किया जाए।

iii) निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ ने केवल नियुक्ति पत्र जारी करने का मंत्रिस्तरीय कार्य किया। उन्होंने सरकारी आदेशों का पालन करते हुए कार्य किया।

iv) कि याचिकाकर्ता को उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था।

v) याचिकाकर्ता के प्रतिनियुक्ति पर होने की अवधारणा इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि याचिकाकर्ताओं की यह पहली नियुक्ति थी.

मूल विभाग और जिस विभाग में किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाना है, उसकी अवधारणा इस मामले में गायब है।

vi) व्यवसाय के नियमों के आधार पर बताया गया बारीक अंतर कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन राज्य के वकील द्वारा पेश किए गए तर्क को बनाए रखने के लिए कोई तथ्यात्मक आधार नहीं रखा गया है।

vii) यह आदेश उस अवधि के दौरान पारित किया गया जब आदर्श आचार संहिता लागू थी और जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, वह भी कानून के अनुरूप नहीं था।

तदनुसार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.1.1998 को रद्द कर दिया।

12. 28.5.1998 को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट, राज्य सरकार ने लैटर पेटेंट अपील को प्राथमिकता दी। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि लेटर्स पेटेंट अपीलों का निपटारा करते समय, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए सामान्य निर्णय को 24.2.2006 को डिवीजन बेंच द्वारा रद्द कर दिया गया था। हमारे समक्ष अपीलकर्ताओं ने 24.2.2006 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी है।

13. तत्काल सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित की जाने वाली पहली सिविल अपील डॉ. कवि राज और अन्य द्वारा दायर की गई है, जबकि दूसरी डॉ. रेवा गैंद और अन्य द्वारा दायर की गई है।अपीलकर्ताओं के वकील ने शुरुआत में ही हमें सूचित किया कि पहली सिविल अपील केवल पांच अपीलकर्ताओं, अर्थात् डॉ. कंचन आनंद, डॉ. अर्पणा शर्मा, डॉ. मेहबूबा बेगम, डॉ. निधि शर्मा और डॉ. के संबंध में बची है। शमा परवीन भट्ट। दूसरी सिविल अपील के विपरीत, यह कहा गया कि यह केवल डॉ.रेवा गैंद, डॉ.रचना वट्टल, डॉ.माला मंडला, डॉ.करुणा वज़ीर, डॉ.इला गुप्ता,

डॉ.सिमी कंधारी, डॉ.इंदु के संबंध में जीवित है। रैना, डॉ. शिवानी मल्होत्रा और डॉ. सुरेखा भट्ट।इसलिए यह स्पष्ट है कि वर्तमान में दो सिविल अपीलें केवल 14 अपीलकर्ताओं के संबंध में ही जीवित हैं, जिनका पूरा विवरण ऊपर दिया गया है।

14. अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज करने के लिए, विद्वान वकील ने हमारा ध्यान प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज, जम्मू के दिनांक 30.12.1997 के आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसके तहत, अपीलकर्ताओं को अलग-अलग विभागों में सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में उनकी पहली पदस्थापन्न सौंपी गई थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू के विभाग (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में)। इसके आधार पर, विद्वान वकील का जोरदार तर्क था कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह मानने में गंभीर गलती की कि अपीलकर्ताओं को सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्त किया गया था। इस तर्क को आगे बढ़ाने के लिए, कि अपीलकर्ताओं को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में नियुक्त नहीं किया गया था, यह बताया गया कि सहायक सर्जन के पद जिनके खिलाफ अपीलकर्ताओं को नियुक्त किया गया था, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए थे। सहायक सर्जनों के 1255 पदों को भरने की मांग भी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग को भेजी गई थी। यह प्रचारित करने की मांग की गई थी कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू, स्वास्थ्य और चिकित्सा

शिक्षा विभाग का एक हिस्सा था, और इस तरह, यह प्रस्तुत किया गया था, कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न की जाए। (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) को प्रतिनियुक्ति के माध्यम से की गई पदस्थापन्न नहीं माना जा सकता है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न को उस कैडर के अलावा किसी अन्य कैडर में नहीं माना जा सकता है जिसमें उन्हें मूल रूप से नियुक्त किया गया था। उपरोक्त दलील के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह सुझाव देने का प्रयास किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष पूरी तरह से उचित थे, और कानून के अनुरूप थे। विद्वान वकील ने तदनुसार प्रार्थना की कि दिनांक 24.2.2006 के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया जाए।

15. अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के हाथों प्रस्तुत प्रस्तुति के अलावा, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में देखा गया है, यह भी उनका जोरदार तर्क था, कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप थी राज्य सरकार। इस संबंध में, विद्वान वकील ने सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 पर भरोसा जताया, जिसके तहत सहायक सर्जन के पद के लिए नए चयनित उम्मीदवारों के पदस्थापन्न आदेश जारी करने के मानदंड निर्धारित किए गए थे। उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 (यहां ऊपर पैराग्राफ 4 में निकाला गया) के पैराग्राफ 5 (एफ) पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में रिक्तियों

के खिलाफ अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न स्पष्ट रूप से के दायरे में थी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में पदों पर उनका चयन। चूंकि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न सरकारी आदेश दिनांक 17.7.1997 के अनुरूप की गई थी, इसलिए यह तर्क दिया गया कि यह अनुमान लगाना स्वाभाविक था कि यह उसी कैडर के भीतर था जिसमें उन्हें चुना और नियुक्त किया गया था। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया कि प्रिंसिपल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.1.1998 को एक गलतफहमी पर जारी किया गया माना जाना चाहिए, कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और /या उससे संबद्ध अस्पताल) उनकी वैध पदस्थापन्न के दायरे से बाहर था। उपरोक्त कारण से भी, यह तर्क दिया गया कि दिनांक 7.1.1998 के आक्षेपित आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है।

16. हम उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णय के समान ही अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुति को भी रिकॉर्ड पर रख सकते हैं। पुनरावृत्ति से बचने के लिए, उपरोक्त पैराग्राफ 8 का संदर्भ लिया जा सकता है। विद्वान वकील ने उपरोक्त तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति का समर्थन किया।

17. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दी गई दलीलों के जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के हाथों दिए गए तर्क,

हालांकि सुनवाई के दौरान विस्तृत थे, एक सिंहावलोकन के लिए यहां संक्षेप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं:

i) स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग में दो स्वतंत्र निदेशालय शामिल हैं, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय। सहायक सर्जन के पद, जिनके विरुद्ध अपीलकर्ताओं का चयन और नियुक्ति की गई थी, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत पदों के कैडर के थे।

ii) जबकि, अपीलकर्ताओं के चयन और नियुक्ति के समय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के पास सहायक सर्जनों का एक कैडर था, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, जिसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पताल) शामिल थे, सहायक सर्जन का कोई पद नहीं था। इसलिए, अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न, सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) केवल प्रतिनियुक्ति के माध्यम से ही हो सकती थी।

iii) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले संवर्गों के साथ-साथ, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत आने वाले संवर्गों को अलग-अलग नियमों द्वारा विनियमित किया जाता है। जबकि जम्मू और कश्मीर चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1979, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं; जम्मू और कश्मीर चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा

भर्ती नियम, 1970 स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में राजपत्रित कर्मचारियों की भर्ती को विनियमित करते हैं।

ऊपर उल्लिखित 1979 के नियमों के तहत, सहायक सर्जन का कोई पद नहीं था। इसलिए सहायक सर्जन के पद, स्पष्ट रूप से चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के तहत पदों के कैडर में शामिल नहीं थे। यह भी बताया गया कि

सहायक सर्जन का पद ऊपर उल्लिखित 1970 के नियमों में शामिल है, और इस प्रकार, सहायक सर्जन के पद, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत पदों के कैडर में एक निश्चित स्थान पाते हैं। उपरोक्त तथ्यात्मक/कानूनी स्थिति से यह अनुमान लगाने की कोशिश की गई थी कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में थी, और उनकी पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) थी। प्रतिनियुक्ति का तरीका.

iv) डिवीजन बेंच दिनांक 24.2.2006 द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए, यह बताया गया कि इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं ने उसमें दर्ज एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति पर विवाद नहीं किया था, अर्थात्, अपीलकर्ताओं का वेतन आहरित होता रहा। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से, उस पूरी अवधि के लिए, जिसके दौरान अपीलकर्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में सेवा प्रदान कर रहे थे। यह प्रस्तुत किया गया कि यह तथ्यात्मक

स्थिति यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में थी, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में।

18. प्रतिद्वंद्वी पक्षों के विद्वान वकील के हाथों दी गई दलीलों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उत्तरदाताओं की ओर से दी गई दलीलें, जैसा कि ऊपर संक्षेप में बताया गया है, अपरिहार्य हैं। इसलिए, हमारे लिए यह स्वीकार करना संभव नहीं है कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति मूल रूप से चिकित्सा शिक्षा निदेशक के तहत एक कैडर में की गई थी। हमारा यह भी विचार है कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्पष्ट रूप से प्रतिनियुक्ति के माध्यम से हुई थी। सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में

उनकी पदस्थापन्न निश्चित रूप से उनके मूल कैडर से परे थी, और इसलिए, प्रतिनियुक्ति के माध्यम से। हमारे उपरोक्त निष्कर्षों के कारणों को निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्ज किया जा रहा है।

19. हालांकि यह स्पष्ट है कि सहायक सर्जन के पद राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा बनाए गए थे, यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त विभाग में दो स्वतंत्र निदेशालय शामिल हैं, अर्थात् स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय। दोनों निदेशालयों में से प्रत्येक के कर्मचारी नियमों के एक अलग सेट द्वारा शासित होते हैं। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियमों में सहायक सर्जन के पद नहीं हैं। सहायक सर्जन

का कैडर केवल स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के राजपत्रित कर्मचारियों पर लागू भर्ती नियमों में पाया जाता है। दूसरे, प्रतिवादियों के विद्वान वकील के हाथों यह दावा किया गया कि जब अपीलकर्ताओं का चयन किया गया और उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) में तैनात किया गया तो सहायक सर्जन के कोई पद नहीं थे। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय पर विवाद नहीं किया गया है। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में सहायक सर्जन के किसी भी पद के अभाव में, यह अनुमान लगाना असंभव है कि अपीलकर्ता (जिन्हें सहायक सर्जन के पदों के विरुद्ध चुना गया था) चिकित्सा शिक्षा निदेशालय से संबंधित हो सकते हैं। इसके अलावा, लोक सेवा आयोग द्वारा अपीलकर्ताओं के चयन के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 12.8.1997 को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। उपरोक्त नियुक्ति आदेश का एक प्रासंगिक उद्धरण ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकन से पता चलता है कि जिन उम्मीदवारों को सहायक सर्जन के रूप में चुना गया था, और वे जम्मू क्षेत्र से थे, उन्हें निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू को रिपोर्ट करना था। जबकि, कश्मीर क्षेत्र से संबंधित लोगों को निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, कश्मीर को रिपोर्ट करना था। जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक,

संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशालयों में प्रशासनिक कमान श्रृंखला के प्रभारी माने जाते हैं। यह स्वयं प्रदर्शित करता है, कि अपीलकर्ताओं की नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में थी, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में। चौथा, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट

मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा दिनांक 30.12.1997 को जारी आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं को सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में तैनात किया जा रहा था। सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के पद सहायक सर्जन के पदों से अलग और अलग हैं। सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के पद चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के पदों के कैडर में शामिल हैं। अपीलकर्ताओं की सीनियर/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में पदस्थापन्न यह भी दर्शाती है कि उनकी नियुक्ति स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के भीतर नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के बाहर के पदों पर थी। इसके अलावा, दिनांक 7.1.1998 के आक्षेपित आदेश में भी कहा गया है कि अपीलकर्ताओं को अस्थायी रूप से तैनात किया जा रहा था "... स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से, जम्मू..." सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में डॉक्टरों की कमी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। छठा, आदेश दिनांक 7.1.1998 (ऊपर पैराग्राफ 5 में निकाला गया) के क्रम संख्या 2 पर समर्थन से पता चलता है, कि निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, जम्मू द्वारा एक अनुरोध किया गया था कि अपीलकर्ताओं को निदेशालय में वापस भेज दिया जाए। स्वास्थ्य सेवाएँ, उक्त सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। सातवें, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के दिनांक 20.4.1998 के आदेश से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं की पदस्थापन्न सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में) स्वास्थ्य सेवाओं के दो निदेशकों द्वारा की गई थी। सरकारी आदेशों का

उल्लंघन करते हुए, उस उद्देश्य को विफल कर दिया जिसके लिए अपीलकर्ताओं को चुना और नियुक्त किया गया था। अंत में, प्रतिवादियों के विद्वान वकील का यह अखण्डित दावा है कि अपीलकर्ताओं का वेतन उस पूरी अवधि के लिए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय से लिया जाता रहा, जिस अवधि के दौरान अपीलकर्ता सरकारी मेडिकल कॉलेज में तैनात रहे। जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों में)। यदि अपीलकर्ता वैध रूप से अपने कैडर के भीतर काम कर रहे होते,

तो उनका वेतन निस्संदेह चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के फंड से आहरित होता। यह तथ्यात्मक स्थिति मामले पर अंतिम मुहर लगाती है, क्योंकि यह किसी और कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के कोष से अपीलकर्ताओं को वेतन के संवितरण के आधार पर, अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहायक सर्जन के कैडर का मूल कर्मचारी माना जाना चाहिए। इसलिए इसमें किसी भी संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि अपीलकर्ताओं को वास्तविक रूप से स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में नियुक्त किया गया था, न कि चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में।

20. निष्कर्ष से पहले, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्षों से निपटना आवश्यक है। विद्वान एकल न्यायाधीश के अनुसार, किसी कर्मचारी को उसके मूल विभाग के बाहर प्रतिनियुक्ति पर तैनात करने से पहले उसकी पूर्व सहमति अनिवार्य, बाध्यकारी, अनिवार्य और अनिवार्य है। हमारे संज्ञान में ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं लाया गया है, जिसमें किसी कर्मचारी को

उसके मूल कैडर से बाहर किसी पद पर तैनाती से पहले उसकी पूर्व सहमति की आवश्यकता हो। केवल तथ्य, कि सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में उनकी पदस्थापन्न से पहले अपीलकर्ताओं की सहमति नहीं मांगी गई थी, हमारे विचार से वर्तमान विवाद पर कोई निर्णायक प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोटे तौर पर, किसी कर्मचारी को केवल उसी पद पर तैनात (या स्थानांतरित) किया जा सकता है जिसके लिए उसका चयन किया गया हो। इससे उनके प्रमुख नियोक्ता के तहत पदों के कैडर के भीतर उनकी तैनाती सुनिश्चित हो जाएगी। हालाँकि, उनकी पदस्थापन्न को उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों द्वारा अलग-अलग तरीके से विनियमित किया जा सकता है। ऐसे किसी भी नियम के अभाव में, किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा/तत्परता के बिना उस कैडर से बाहर तैनात (या स्थानांतरित) नहीं किया जा सकता है, जिसके लिए उसका चयन किया गया है। इसलिए, किसी कर्मचारी की उसकी इच्छा के विरुद्ध, जिस विभाग में उसकी नियुक्ति हुई है, उसके अलावा किसी अन्य विभाग में उसकी पदस्थापन्न (या स्थानांतरण) अस्वीकार्य होगी। लेकिन कैडर (और/या मूल विभाग) से परे पदस्थापन्न की इच्छा स्पष्ट रूप से मांगी जाने की आवश्यकता नहीं है। यह निहित किया जा सकता है इसे लिखित सहमति की प्रकृति की आवश्यकता नहीं है।

कैडर (या मूल विभाग) से परे पदस्थापन्न (या स्थानांतरण) की सहमति का अनुमान कर्मचारी के आचरण से लगाया जा सकता है, जो ऐसी

पदस्थापन्न/स्थानांतरण का विरोध या विरोध नहीं करता है। वर्तमान विवाद में, अपीलकर्ताओं को प्रिंसिपल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू द्वारा दिनांक 30.12.1997 को पदस्थापन्न आदेश जारी किए गए थे। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, और सहायक सर्जन के रूप में चयन और नियुक्ति के बावजूद, सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू में वरिष्ठ/जूनियर हाउस ऑफिसर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। अब भी, वे चिकित्सा शिक्षा संचालनालय में पदों के विरुद्ध सेवा जारी रखना चाहते हैं। उधार निदेशालय के साथ सेवा करने की उनकी इच्छा/तत्परता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। अपीलकर्ताओं की सहमति मौन और निर्विवाद है। इसलिए हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले के तात्कालिक पहलू पर स्पष्ट रूप से गलती की है।

21. यहां ऊपर व्यक्त किए गए कारणों से, हम संतुष्ट हैं, कि 24.2.2006 को उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा पारित आदेश, किसी भी तथ्यात्मक या कानूनी कमजोरी से ग्रस्त नहीं है।अत: इसकी पुष्टि की जाती है।

22. विवाद के गुण-दोष पर अपने निष्कर्ष दर्ज करने के बावजूद, हमारे लिए अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दी गई तकनीकी दलील पर विचार करना भी आवश्यक है। अपीलकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि विद्वान एकल न्यायाधीश (दिनांक 28.5.1998) के फैसले के परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को दिनांक 7.1.1998 को प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन का आदेश

दिया गया था। एक तरफ, दो पत्र पेटेंट अपीलें, यानी, 2000 की एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 88, और 2000 की एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 89, उत्तरदाताओं द्वारा यहां दायर की गई थीं (विद्वानों द्वारा पारित सामान्य आदेश दिनांक 28.5.1998 को चुनौती देने के लिए) एकल न्यायाधीश)। उपरोक्त पत्र पेटेंट अपील के पहले में, 18 सहायक सर्जनों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, जबकि, दूसरे पत्र पेटेंट अपील में 24 सहायक सर्जन को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था। यह बताया गया कि 2000 की लेटर्स पेटेंट अपील (एसडब्ल्यू) संख्या 88 को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। उक्त लेटर्स पेटेंट अपील को कभी भी बहाल नहीं किया गया था। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि 28.5.1998 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 18 सहायक सर्जनों (उसमें उत्तरदाताओं के रूप में शामिल) से संबंधित पारित आदेश को अंतिम रूप दिया गया। उपरोक्त निर्विवाद स्थिति के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था, कि राज्य सरकार के लिए अब यह अनिवार्य है कि वह उपरोक्त 18 सहायक सर्जनों (प्रतिवादी के रूप में शामिल) के संबंध में दिनांक 28.5.1998 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को प्रभावी करे। एलपीए(एसडब्ल्यू) क्रमांक 88 ऑफ़ 2000)। मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण में, यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि 18 सहायक सर्जनों के संबंध में बाध्यकारी प्रभाव को शेष 24 सहायक सर्जनों तक बढ़ाया जाना चाहिए (जिन्हें एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या

89 में प्रतिवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2000. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के अनुसार, यह न्याय के उद्देश्यों को भी पूरा करेगा, क्योंकि समान रूप से स्थित सभी व्यक्तियों को समान रूप से रखा जाना चाहिए। विद्वान वकील के अनुसार, यदि इस स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो अपीलकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत गारंटीकृत कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे।

23 हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों दी गई उपरोक्त तकनीकी दलील पर विचारपूर्वक विचार किया है। यह विवाद का विषय नहीं है, कि 2000 के एलपीए (एसडब्ल्यू) नंबर 89 पर डिवीजन बेंच ने योग्यता के आधार पर फैसला सुनाया था। हमारे द्वारा पारित तत्काल आदेश के संदर्भ में, हमने 24.2.2006 को उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा पारित आदेश की शुद्धता की पुष्टि की है। इस प्रकार देखने पर, यह स्पष्ट है कि 24 सहायक सर्जनों के संबंध में डिवीजन बेंच द्वारा विवाद का उचित निर्णय लिया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील के हाथों उन्नत तकनीकी दलील से निपटने के दौरान निर्णय लिया जाने वाला एकमात्र प्रश्न यह है कि क्या 2000 के एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या 88 में दिए गए फैसले को एलपीए (एसडब्ल्यू) संख्या तक बढ़ाया जाना चाहिए। 2000 का 89. या इसके विपरीत, क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश, जो 18 सहायक सर्जनों के संबंध में अंतिम रूप ले चुका है, को अन्य 24 सहायक सर्जनों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

24. जहां तक 24 सहायक सर्जनों से संबंधित मामले का संबंध है, 24.2.2006 को उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की हमारे द्वारा गुण-दोष के आधार पर पुष्टि की गई है। इसलिए यह अनुमान लगाना वैध है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा मामले का गलत निर्णय लिया गया है। हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा 24 सहायक सर्जनों (जिनका दावा दिनांक 24.2.2006 के आक्षेपित आदेश द्वारा तय किया गया था) से संबंधित विवाद का निर्णय कानून की घोषणा का गठन करता है, और अनुच्छेद 141 के तहत बाध्यकारी है। भारत का संविधान. 24 सहायक सर्जनों (जिनके दावे पर उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा फैसला सुनाया गया था) के संबंध में दिए गए निर्धारण का कद देखते हुए, हमारा विचार है कि यदि अनुमति हो तो इसे अन्य 18 सहायकों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। सर्जन. आमतौर पर, ऐसी स्थिति में जब प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच कोई निर्णय अंतिम हो जाता है, तो मुद्दे को फिर से खोलना वैध नहीं है, यहां तक कि किसी त्रुटि को सुधारने के लिए भी, जो बाद के निर्णय से उत्पन्न होती है।

25. मौजूदा विवाद में तथ्यात्मक स्थिति थोड़ी अलग है. इस न्यायालय के समक्ष दो विशेष अनुमति याचिकाएँ दायर की गईं। जिन सहायक सर्जनों के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी, वे भी इस न्यायालय के समक्ष हैं। उन्हें सुनवाई का अवसर भी दिया गया है। इस न्यायालय ने राय व्यक्त की है कि 24.2.2006 को उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट बेंच द्वारा पारित आदेश बरकरार

रखा जाना चाहिए। यदि सहायक सर्जन जिनके पत्र पेटेंट अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था, इस न्यायालय के समक्ष नहीं थे, तो हमारे लिए उनके दावे पर फिर से निर्णय लेना संभव नहीं हो सकता था। चूंकि वे सभी हमारे सामने हैं, और उन्हें परामर्श के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि तत्काल विवाद में योग्यता के आधार पर निर्णय उन तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। चूँकि इस तरह का विकल्प वर्तमान मामले में किया जा सकता है, हमारा विचार है कि जिस प्रस्ताव को कानूनी माना गया है, उसे समान रूप से स्थित अन्य लोगों तक भी बढ़ाया जाना चाहिए। उलटा प्रस्ताव, स्वीकृति के लिए स्वयं की सराहना नहीं करता है। उस आदेश को लागू करना अकल्पनीय होगा, जिसे उचित नोटिस और सुनवाई के बाद रद्द कर दिया गया है। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई तकनीकी दलील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

26. अपीलकर्ताओं को उनके मूल विभाग, यानी स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में प्रत्यावर्तन/प्रत्यावर्तन की पुष्टि की जाती है। जिन अपीलकर्ताओं ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू (और/या उससे जुड़े अस्पतालों) में सेवा में शामिल होने के बाद से अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा है, उन्हें स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, जम्मू में वापस भेज दिया जाएगा। अब, जब मामला अंतिम रूप ले चुका है, तो उन्हें निदेशालय चिकित्सा शिक्षा में उनकी पदस्थापन्न से मुक्त किया जाना चाहिए। उन्हें स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करने में सक्षम बनाने और हमारे आदेश से उभरने

वाली स्थिति के साथ उन्हें अनुकूलित करने के लिए, हम यह निर्देश देना न्यायसगंत और उचित मानते हैं कि अपीलकर्ताओं को 31.3.2013 तक उनके वर्तमान पदस्थापन्न स्थान पर बने रहने की अनुमति दी जाए। उन्हें निदेशालय स्वास्थ्य सेवा में एक संवर्ग पद पर आगे की पदस्थापन्न के लिए 31.3.2013 की दोपहर को सभी परिस्थितियों में चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में उनकी पदस्थापन्न से मुक्त कर दिया जाएगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार निस्तारण किया गया।

अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नीरज कुमार **(**आर.जे.एस.**)** द्वारा किया गया है।

अस्वीकारण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेंजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।